This House must ask itself: Should Odisha forever remain the silent sentinel expected to give but not to get? Hon. Deputy Chairman, Sir, this is a national test of fairness. This is no longer a routine demand. This is a test, a test of our nation's commitment to justice, equity and federal responsibility. Odisha has shown resilience. Odisha has shown contribution, and I firmly demand that Odisha must be given Special Category status. *Vande Utkal Janani*! Jai Odisha! Jai Hind!

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Telangana): We all associate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Shri Shaktisinh Gohil — 'Concern over the incidence of fire in the textile market of Surat, Gujarat'. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sir, give me a minute...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. I have given the floor to the next speaker. ...*(Interruptions)*... I have not given permission to you. Please...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Since we are not being heard, we stage a walk out ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

Concern over the incidence of fire incident in the Textile Market of Surat, Gujarat

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर हादसे के बारे में आपके ज़रिये इस गृह और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, गुजरात के सूरत में शिवशक्ति टैक्सटाइल मार्किट है। उसमें बुरी तरह से आग लगी। महोदय, टैक्सटाइल उद्योग से छोटे-छोटे व्यापारी जुड़े होते हैं और आजकल टैक्सटाइल में मंदी का माहौल होने की वजह से सभी के पास स्टॉक भी था। महोदय, जो आग लगी, उसमें 900 दुकानें जलकर राख हो गईं और सबसे दुख भरी बात तो यह है कि उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला। महोदय, क्योंकि वे

छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनके पास इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनके पास नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से सहायता पहुंचनी चाहिए।

महोदय, एक हकीकत यह भी है कि वहाँ पर किस तरह से लापहवाही की गई। वहाँ दोपहर में 1.30 बजे आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है, पुलिस के ऑफिसर्स आते हैं और 'आग कंट्रोल में आ गई है' - ऐसा कहकर शाम को चले जाते हैं, लेकिन वहाँ धुआँ निकल रहा होता है। लोग कहते हैं कि 'सर, देखिए अभी भी धुआँ निकल रहा है', लेकिन वे चले गए और रात को 1 बजे फिर से आग लगी और बहुत बड़े पैमाने पर लगी। अगर वह लापरवाही नहीं की गई होती, और वे ऑफिसर्स, जो दोपहर में 1.30 बजे आए थे, वे व्यवस्था ठीक करके जाते, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।

महोदय, इससे पहले 2020 में भी इसी तरह से एक टैक्सटाइल मार्किट में बुरी तरह से हादसा हुआ था। वहाँ से सरकार को सीख लेनी चाहिए थी कि दोबारा ऐसे हादसे नहीं हों। उपसभापति महोदय, मेरा आपके ज़रिये सरकार से अनुरोध है कि गुजरात में दोबारा ऐसे हादसे न हों, इसके लिए प्रिकॉशन्स लिए जाएं।

महोदय, फायर विभाग से जुड़े एक अधिकारी से मेरी बात हुई थी। वे कहते हैं कि तक्षशिला में जो पहले हुआ, उसके बाद यह भी हुआ और यहाँ पर यह कहूंगा कि फायर के वक्त जब सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल केमिकल आता है, जो पानी में मिलाकर लगाना चाहिए, लेकिन उसका पूरा स्टॉक हमारे पास नहीं था। महोदय, यह जरूरी है कि सूरत जैसा शहर, हमारी आर्थिक राजधानी जैसा शहर, जो देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाने में भी काम करता है और बहुत टैक्स देता है, उस सूरत शहर के लिए हमारी ज्यादा चिंता होनी चाहिए। मैंने पर्सनली फोन पर तो नहीं कहा - क्योंकि मिलना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी जी को टैग करके कहा था कि आप सूरत जा रहे हैं, इसलिए उस मार्किट में जरूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि गुजरात में किस तरह के हालात हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर रोड शो हुआ, वे वहाँ गए भी, लेकिन उन्होंने उस टैक्सटाइल मार्किट को देखा नहीं है। मैं आपके ज़रिये सरकार से गुज़ारिश करता हूं कि ये छोटे व्यापारी हैं, इसलिए उनकी चिंता की जाए और उन्हें मुआवज़ा दिया जाए। महोदय, मुझे आपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member Shri Shaktisinh Gohil: Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Mukul Balkrishna Wasnik (Rajasthan), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Sanjay Singh (National Capital Territory of Delhi), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Imran Pratapgarhi (Maharashtra) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Dr. Kalpana Saini - 'Demand to strengthen sports infrastructure in Uttarakhand and to develop it as a hub for international sports events'.

Demand to strengthen the sports infrastructure in Uttarakhand and to develop it as a hub for international sports events

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और वीरता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कई प्रमुख तीर्थ स्थल और मंदिर होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। हाल में राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड की पूरे देश में सराहना हो रही है। महोदय, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, इको फ्रेंडली आयोजन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि खेलभूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। महोदय, यहाँ के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और क्षमता देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उत्तराखंड राज्य को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को मजबूत करते हुए भारत की संस्कृति, परंपराओं और खेल प्रतिभा का उत्सव मनाने का एक प्रभावी मंच है।

भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य में खेल अर्थव्यवस्था एक प्रभावी भूमिका निभा रही है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए खेलों के प्रति एक सुव्यवस्थित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 2036 ओलम्पिक के मेजबानी के अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ इच्छा रखती है। यह ऐतिहासिक पहल न केवल भारतीय खेल जगत को वैश्विक जगत पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि इससे बुनियादी ढांचे, पर्यटन, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए असीम संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी। साथ ही यह आयोजन देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और जलवायु इसे पर्वतीय खेलों, एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती है। यदि यहां अंतरराष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो इससे न केवल राज्य की ख्याति बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र में स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। इसके तहत विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून, औली और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाए। उत्तराखंड पहले से ही ट्रैकिंग, राफ्टिंग और पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर राज्य को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की सफल ...**समय की घंटी**)...